SHAKUNTALAM INSTITUTE OF TEACHERS EDUCATION

KIRHINDIH, KUMHAU STATION ROAD, SHIVSAGAR

COURSE NAME – B.Ed. 1st year SESSION – 2021-2023

SUBJECT - भारतीय शिक्षा का इतिहास

TOPIC NAME – बिहार में शिक्षा का ऐतिहासिक विकास, सभी के लिए शिक्षा व्यवस्था,

DATE - 3/02/2022

Unit - 2

PAGE NO.
DATE :

बिहार में शिक्षा का ऐतिहासिक विकास ⇒

उच्च शिक्षा के लिए जिस तरह बिहार में हाय तौबा मच रही है और केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिए जिस तरह नीतीश जी की ओर आजमाइश चल रही है, उससे एक बात तो हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या इससे बिहार में शिक्षा का कुछ सुधार होगा। क्या फिर से बिहार शिक्षा में वही मुकाम हासिल कर पायेगा जहाँ कभी ये हुआ करता था। क्या बिहार विकास का नारा देने वाले शिक्षा के क्षेत्र में भी इसे अगली पंक्ति में खड़ा कर पायेंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं बिहार में अगर शिक्षा के इतिहास पर नजर डालें तो इसे सिर्फ कुचलने वाले ही मिलेंगे। उंगलियों पर गिनने वाले ही ऐसे मिलेंगे जिसने बिहार में शिक्षा के लिए कुछ काम किया है। सन् 1213 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को बर्बाद कर बिहार के शिक्षा की संस्कृति को तबाह ही कर डाला, फिर अंग्रेजों की बारी आई और उसने ऐसी नीति बनाई की बिहार शिक्षा के क्षेत्र में काफी पीछे छूट गया। अंग्रेजों ने जैसी नींव रखी थी वैसी ही इमारत भी खड़ी हुई और आजादी के बाद राजनैतिक अराजकता ने इसे गर्त में धकेल दिया यहाँ तक कि पटना विश्वविद्यालय जो कि देश का सातवाँ पुराना विश्वविद्यालय है की भी

PAGE NO.
DATE :

गरिमा खत्म हो गई। रही सही कसर बाद में संयुक्त विधायक दल सरकार और बिहार आन्दोलन ने पूरी कर दी। जगन्नाथ मिश्र, महामाया प्रसाद से लेकर लालू प्रसाद यादव तक पालतूकरण की नीति अपनाकर विश्वविद्यालयों को अपना राजनैतिक चारागाह बना दिया। शिक्षा में व्याप्त राजनीति और गुंडाराज को देखकर शिक्षाविद डॉ॰ वी॰एस॰ झा ने तो यहाँ तक कह दिया कि " बिहार में महाविद्यालय स्थापित करना एक लाभप्रद धंधा है बशर्ते कि संस्थापक राजनैतिक बॉस हो या जनता की नजर में उनकी छवि के गुंडे की हो।

बाद के समय में शिक्षामंत्री कर्पूरी ठाकुर ने आदेश दे दिया कि मैट्रिक में पास होने के अंग्रेजी अनिवार्य विषय नहीं होगी। विदाउट इंगलिश को कर्पूरी डिवीजन नाम दिया गया फलतः बिहार में अंग्रेजी का स्तर इतना गिर गया जो आज भी देखने को मिलता है। बाद के समय में केदार पाण्डेय ने विश्वविद्यालय से गुंडाराज खत्म करने के लिए कुछ ठोस और साहसिक कदम उठाए। उनकी सरकार ने विश्वविद्यालय का जिम्मा अपने हस्तगत किया और सख्त आई॰ए॰एस अधिकारियों को कुलपति और रजिस्ट्रार के पद पर बहाल किया। इससे परीक्षाएँ और कक्षाएँ बंदूकों के साए में होने लगी और शिक्षा की संस्कृति पटरी पर लौटने लगी।

PAGE NO.
DATE :

लेकिन शायद बिहार की शिक्षा को किसी की नजर लग गई थी या कुछ और इसलिए संपूर्ण क्रांति का दौर आ गया और शिक्षा की व्यवस्था संपूर्ण क्रांति में दबकर रह गयी।

फिर 1980 में जगन्नाथ मिश्र सत्ता में आए और उर्दू को राजभाषा का दर्जा दे दिया। बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने उर्दू को राजभाषा का दर्जा दिया। इस कदम ने मैथिली को काफी पीछे धकेल दिया। वहीं मुस्लिम के बीच वो हीरो बन गए। आज अगर बिहार में मैथिली की हालत बदतर है फिर लालू का दौर आया उन्होंने चरवाहा विद्यालयों के रूप में दलित समाज के लोगों को आगे उठाने का काम किया लेकिन उनकी यह योजना भी राजनीतिक अस्थिरता और सत्ता परिवर्तन के कारण फ्लाप हो गई फिर नीतिश का राज आया उम्मीदें जगी शिक्षा के क्षेत्र में फिर भी उस कदर काम नहीं हुआ जिस कदर होना चाहिए। नीतिश राज में जिस तरह बिहार नित नए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिकार्ड तोड़ रहा है उसमें जनता को शिक्षा के लिए भी कुछ उम्मीदें जगती नजर आ रही थी एक तरफ नीतिश ने पंचायतों में शिक्षा के लिए शिक्षामित्रों की नियुक्ति कर रोजगार के अवसर तो बढ़ा दिए लेकिन नियुक्ति नहीं हो पाई।

बिहार शिक्षा परियोजना

औपचारिक दृष्टि से बिहार जैसे पिछड़े राज्य के लिए केन्द्र द्वारा संचालित बिहार शिक्षा परियोजना शिक्षा के सार्वजनिकरण के क्षेत्र में एक सार्थक प्रयास है। सरकार से राज्य की जनता को विभिन्न प्रकार के माध्यमों के द्वारा विभिन्न परियोजनाओं को शिक्षा के स्तर पर कारगर बनाने के लिए प्रयत्नरत है। इस प्रकार की परियोजनाओं की परिकल्पना इसलिए भी की गई है क्योंकि राज्य की शिक्षा की प्रगति दर एवं प्रतिशत बहुत उत्साहवर्द्धक नहीं है। जब तक शिक्षा जन जन की शिक्षा नहीं बन पाती तब तक आम जनता के जीवन स्तर में सुधार नितान्त असम्भव है जो व्यक्ति निरक्षर आर्थिक विपन्नता से ग्रसित सामाजिक उत्पीड़न से जूझ रहा है उन्हें शिक्षा की रोशनी देना परम आवश्यक है ताकि उनकी जिन्दगी भी प्रकाशित हो सके। अनु० जाति, जन जाति, महिलाएँ, बच्चे आदि को कम से कम प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्रदान किया जाए।

इसीलिए बिहार शिक्षा परियोजना में औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा स्वयंसेवी संस्था द्वारा संचालित अन्य गैर सरकारी संस्थाओं का भी सहयोग लिया जा रहा है।

बिहार शिक्षा परियोजना के प्रमुख लक्ष्य ⇒

(1) सर्वव्यापक भागीदारी
(2) सर्वव्यापक : जन जन तक पहुँच
(3) शिक्षा वंचित महिला वर्ग, अनु जाति, अनु जनजाति को शिक्षा प्रदान करना।
(4) शिक्षा के स्वरूप को आकर्षक एवं प्रभावी बनाना
(5) विद्यालय को आकर्षक बनाना।
(6) शिक्षा के स्वरूप एवं प्रक्रिया में मूलभूत परिवर्तन हो सके।
(7) शिक्षा में गुणवत्ता का प्रवेश एवं प्रभाव दोनों ही संभव हो सके।

बिहार शिक्षा परियोजना, जिलास्तर पर स्वैच्छिक संस्थाएँ एवं अन्य सरकारी संस्थाएँ ब्राइट तथा डी० आर० यू० जैसी प्रशिक्षण संस्थाएँ भी बिहार के अनेक जिलों में चलाई जा रही हैं। बिहार शिक्षा परियोजना परिवेश में आशय परन्तु क्रमिक सुधार करके बिहार के प्राचीन गौरव को प्राप्त करने की दिशा में सार्थक प्रयास है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का गठन 1 सितम्बर 1961 को सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में किया गया था।

वर्तमान में यह संस्था मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तकनीकी संस्था के रूप में कार्य करती है। केन्द्र सरकार इस परिषद के अनुरक्षण एवं परित्याग का सम्पूर्ण वित्तीय भार वहन करती है। राज्य में इसकी अनुषंगी संस्था राज्य शिक्षा प्रशिक्षण एवं शोध परिषद शिक्षा में सुधार हेतु कार्य करती है।

NCTE राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने NCTE की स्थापना सन् 1977 में की इसकी स्थापना का उद्देश्य सम्पूर्ण देश में अध्यापक शिक्षा का सुनियोजित विकास करना, केन्द्र एवं राज्य सरकारों को शिक्षक शिक्षा के सभी पक्षों पर सलाह देना तथा अध्यापक शिक्षा के लिए निर्धारित मनकों एवं स्तर को बनाए रखना है।

प्रारम्भ में यह एक असंवैधानिक संस्था थी सन् 1993 में लोकसभा के अधिनियम सं० 73 के अंतर्गत इसे संवैधानिक संस्था घोषित कर दिया गया।

शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएँ - राज्य में शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु विभिन्न विश्वविद्यालयों में बी० एड० एवं बेड स्तर से डी० एल० एड० के माध्यम से शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई तथा विश्वविद्यालय द्वारा प्राइवेट संस्थानों को भी सम्बद्धता प्रदान की गई जिससे शिक्षकों के व्यापक प्रशिक्षण की व्यवस्था हो पाई।